भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2299 का उत्तर

बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना

2299. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन को कब तक विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है;

(ख) बरेली से नई रेल लाइनों के निर्माण अथवा एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बरेली में रेल सेवा के विस्तार हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/उन्नयन निरन्तर और सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को आवश्यकतानुसार किया जाता हैं, जो परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन है। कार्यों की स्वीकृति देने और निष्पादन के समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों के विकास/उन्नयन को प्राथमिकता दी जाती है।

हाल के वर्षों में, उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जंक्शन स्टेशन पर यात्री सुविधाओं से संबंधित विभिन्न निर्माण-कार्य निष्पादित किए गए हैं, जिनमें फुट ओवर ब्रिज पर एस्केलेटर की व्यवस्था, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय का उन्नयन आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, बरेली रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास हेतु चिह्नित किया गया है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे

स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडॉल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें से 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:-

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	157	अछनेरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ऐशबाग, अकबरपुर जंक्शन, अलीगढ, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर, आंवला, अयोध्या धाम, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदायूँ, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराइच, बलिया, बालामऊ, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जंक्शन, बरेली जं., बरेली सिटी, बढ़नी, बस्ती, बेल्थरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकूट धाम कर्वी, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दर्शननगर, देवरिया सदर, धामपुर, दिलदारनगर, इटावा जं., फर्रुखाबाद, फतेहाबाद, फ़तेहपुर, फ़तेहपुर सीकरी, फ़िरोज़ाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, गौरीगंज, घाटमपुर, ग़ाज़ियाबाद, ग़ाज़ीपुर सिटी, गोला गोकरननाथ, गोमतीनगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह, इज्जतनगर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज, कासगंज, काशी, खलीलाबाद, खुर्जा जंक्शन,

		कोसी कलां, खोरसनरोड, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग एवं जंक्शन), लखनऊ सिटी, मगहर, महोबा, मैलानी, मैनपुरी जं., मल्हौर जं., मानकनगर जं., मानिकपुर जं., मरियाहू, मथुरा, मऊ, मेरठ सिटी, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद जं., निहालगढ़, उरई, पनकी धाम, फाफामऊ जं., फूलपुर, पीलीभीत, पोखरायां, प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज, पं. दीन दयाल उपाध्याय, रायबरेली जं., राजा की मंडी, रामघाट हॉल्ट, रामपुर, रेनुकूट, सहारनपुर जं., सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज जं., शाहजहाँपुर, शामली, शिकोहाबाद जं., शिवपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर जं., सोनभद्र, श्री कृष्णा नगर, सुल्तानपुर जं., सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला जं., उझानी, ऊंचाहार, उन्नाव जं., उतरेटिया जं., वाराणसी कैंट. वाराणसी सिटी, विंध्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई, व्यासनगर, जाफराबाद.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बरेली स्टेशन के विकास के लिए मास्टर प्लानिंग शुरू कर दी गई है। यह एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है जिसे इष्टतम करने की आवश्यकता होती है और इस स्तर पर इष्टतम करने की समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित अन्य योजनाओं के तहत स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के तहत आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेलवे-

वार रखा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य पांच जोनों अर्थात पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत शामिल है। इन जोनों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 4,188 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का आबंटन किया गया है तथा 2024-25 (जनवरी, 2025 तक) के दौरान 3,202 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार/जिला-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना भारतीय रेल की एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों से संपर्क सहित सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं और निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, बरेली सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 5,874 किमी कुल लंबाई तथा 92,001 करोड़ रुपये लागत वाली 68 रेल परियोजनाएं (16 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 49 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,313 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 28,366 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है। कार्य की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	कमीशन की गई कुल लंबाई (किमी में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रुपये में)
नई लाइन	16	1740	297	8672
आमान परिवर्तन	3	261	0	26
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	49	3873	1016	19668
कुल	68	5874	1313	28366

उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन इस प्रकार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,109 करोड़ रुपये/वर्ष
2024-25	19,848 करोड़ रुपये (17 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और वर्ष 2014-24 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा इस प्रकार है:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	996 कि.मी.	199.2 कि.मी./वर्ष
2014-24	4,902 कि.मी.	490.2 कि.मी./वर्ष (2 गुना से अधिक)

इसके अलावा, सीतापुर - रोज़ा - मुरादाबाद (172 किमी) के बीच तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

वर्तमान में, बरेली को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी, भुज, योग नगरी ऋषिकेश, श्री माता वैष्णो देवी कटरा आदि जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली 87 जोड़ी रेलगाड़ी सेवाओं द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यातायात औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता आदि के अध्यधीन भारतीय रेल पर नई रेलगाड़ी सेवाएं शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है।

*****